मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2021-23 /R.N.I. No. 2022007062

अब पार्कों को कूड़ा निस्तारण केंद्र में बदला जाएगा 2
चंद्रयान तीन की सफलता पर देशवासियों को दी बधाई 4
'समस्त ज्ञान वेद में है' 5
किस दिशा में जा रही है भारतीय राजनीति 6
डीईओ मुनेश चौधरी 31 अगस्त को हुई बाइज्जत रिटायर 8

वर्ष 37 | अंक -42 | फरीदाबाद | 3-9 सितम्बर 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

ईएसआई मेडिकल कॉलेज में अब होंगे किडनी प्रत्यारोपण भी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए, एनएच तीन स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज-अस्पताल शीघ्र ही किडनी प्रत्यारोपण जैसा महत्वपूर्ण काम करने को तैयार हो चुका है। बीते माह नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी (नोटा) ने इस संस्थान का बारीकी से निरीक्षण करने के पश्चात इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इससे पहले भी नोटा की टीम ने यहां का निरीक्षण करके कुछ खामियों की ओर संस्थान का ध्यान आकृष्ट किया था जिन्हें यहां की मेहनती व लगनशील फैकल्टी ने दूर करके नोटा को पुन: आमंत्रित किया था।

नियमानुसार नोटा की सिफारिश पर हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है। अब हरियाणा सरकार के पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो नोटा के निरीक्षण से बढ़कर इस संस्थान की जांच कर सके। इस सरकार के पास ले-दे कर कुछ है तो वह है रोहतक मेडिकल कॉलेज जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। दर्जा भले ही यूनिवर्सिटी का दे दिया गया हो लेकिन कामकाज एवं उत्कृष्टता के मामले में रोहतक का यह संस्थान ईएसआई मेडिकल कॉलेज के सामने कहीं नहीं ठहर पाता। रोहतक से आने वाली टीम के सदस्य अपनी इसी हीनभावना से ग्रस्त होकर सदैव ईएसआई मेडिकल कॉलेज के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करते रहे हैं। चाहे ब्लड बैंक का मामला रहा हो या आई बैंक का या फिर कैथ लैब का या कोई भी काम जब भी इस संस्थान ने करना चाहा हो, रोहतक की टीम ने सदैव अड़ंगे लगाकर ही अपने अहम की संतुष्टि करने का प्रयास किया है।

और तो और उन्हें यहां पर पीजी की बढ़ती सीटों से भी तकलीफ रहती है क्योंकि जो काम रोहतक वाले बीते साठ साल में नहीं कर पाए वे सभी काम ये संस्थान अपने छोटे से यानी सात साल के कार्यकाल में ही करके दिखा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने तथा डीएम के लिए स्वीकृति प्रदान करने के बावजूद रोहतक वालों ने पूरा जोर इन सीटों

असीम दास, डीन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज

की बढ़ोतरी को रोकने पर लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद फैकल्टी एवं डीन के प्रयासों द्वारा बढ़ी हुई सीटें इस संस्थान को मिल ही गई।

हालांकि रोहतक मेडिकल कॉलेज की यह दुर्दशा वहां के स्टाफ या प्रबंधन के कारण नहीं बल्कि इस पर सरकारों की कुदृष्टि रहने के कारण हुई है। चाहे किसी भी दल की सरकार सत्ता में आई उसने मेडिकल कॉलेज की उन्नति करने के बजाय अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने, चाटुकारों को पद देने में ज्यादा रुचि दिखाई।

नतीजा हुआ कि मेडिकल कॉलेज को अच्छे और बेतहरी का फैसला लेने वाले डायरेक्टर की जगह सत्ता के दलाल, बेहतरीन फैकल्टी की जगह अयोग्य चाटुकारों को और स्टाफ की जगह नेताओं के भाई-भतीजों को भर लिया गया। किसी भी संस्था की कामयाबी उसके कुशल मानव संसाधनों पर निर्भर करती है जो रोहतक मेडिकल कॉलेज को स्थायी रूप से कभी हासिल नहीं हो सका, यही कारण है कि अच्छा आधारभूत ढांचा व संसाधन होने के बावजूद रोहतक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बना दिया गया लेकिन वांछित परिणाम नहीं दे पाया।

उन्हें इस बात से भी बड़ी भारी तकलीफ हो रही है कि सर्वोत्तम छात्र जो पहले रोहतक मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता देते थे अब ईएसआई मेडिकल कॉलेज को देने लगे हैं। खैर, जो भी हो, उनकी तमाम अड़ंगेबाजियों के बावजूद हरियाणा सरकार ने इस संस्थान को किडनी प्रत्यारोपण का लाइसेंस जारी कर दिया है। हजारों हृदयरोगियों, सैकड़ों कैंसर रोगियों अनेकों बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वाले मरीजों का सफल इलाज करने के बाद शीघ्र ही किसी न किसी सफल किडनी प्रत्यारोपण की खबर सामने आ सकती है।

किडनी प्रत्यारोपण हो अथवा किसी प्रकार की सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब मज़दूरों को मिलेगा जो सारी उम्र तो ईएसआई को भुगतान करते रहे पर कभी इलाज कराने तक की नौबत तक न आई। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद इस तरह के सुपरस्पेशलिटी इलाज की जरूरत पड़ी तो ईएसआई वाले पल्ला झाड़ लेते थे। दरअसल, कॉरपोरेशन ने नियम यह बना रखा है कि अपने अस्पताल में तो जो मर्जी इलाज कर दो आप रेफर नहीं करोगे। सर्वविदित है कि अपने अस्पतालों में तो होता ही कुछ नहीं था और रेफर करना नहीं तो मज़दूर ने तो मरना ही मरना था लिहाजा अब उन सेवानिवृत्त मज़दूरों को बड़ी राहत मिलेगी जो पूरी सेवाकाल के दौरान ईएसआई को मोटा भुगतान करते रहे। (संबंधित खबर पेज 2 पर)

निगम सचिव ने विज्ञापन हटवा कर केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर से पंगा लिया, मैडम ने छीने अधिकार

मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अमोलिक बिल्डर के अवैध विज्ञापन उखड़वाने का भुगतना पड़ा खामियाजा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर के ड्रीम प्रोजेक्ट अमोलिक बिल्डर के अवैध विज्ञापनों पर बुलडोजर चलाना नगर निगम सचिव जयदीप को महंगा पड़ा। कार्रवाई से नाराज मंत्री के फरमान पर आईएएस टॉपर निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास ने आनन-फानन जयदीप से विज्ञापन विभाग के अधिकार छीन कर विज्ञापनों से मोटी कमाई करने वाले पुराने खिलाड़ी एसई ओमबीर सिंह को सौंप दिया। जयदीप केवल मंत्री की ही आंख में नहीं खटक रहे थे, निगम के खाऊ-कमाई, लूट कमाई में माहिर और बेइमान अधिकारी भी उनकी कार्यशैली से परेशान थे, क्योंकि विज्ञापन तो वह उखड़वा रहे थे लेकिन कमाई इन अधिकारियों की बंद हो रही थी, ऊपर से विज्ञापन माफिया की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही थी।

नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की मोटी कमाई में अवैध विज्ञापन के जरिए आने वाले राशि का बड़ा हिस्सा है। मोटी कमाई के अलावा सत्तापक्ष के नेताओं के विज्ञापन होर्डिंग लगा उनकी चाटुकारिता कर अपनी कुर्सी बचाने का काम भी अधिकारी करते हैं। ग्रेटर फरीदाबाद में अमोलिक बिल्डर नाम की कंपनी के कई बड़े आवासीय, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आम चर्चा है कि यह कंपनी केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर के पौत्र अमोलिक के नाम पर है और वह ही इसके मालिक हैं। अब केंद्रीय मंत्री के प्रोजेक्ट के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग, बैनर, वाल पेंटिंग, खंभों को रंगना ही था। निगम के चाटुकार अधिकारियों ने भी पूरे ग्रेटर फरीदाबाद की सड़कों से लेकर मुख्य स्थान अमोलिक के विज्ञापनों के लिए मुफ्त में छोड़ दिए।

निगम के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा विज्ञापन के जरिए हर साल चार से पांच करोड़ रुपये बंदरबांट करने और डकारे जाने की शिकायतें बीते करीब एक साल से कई आरटीआई कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक कर रहे थे। यहां तक कि पूर्व निगमायुक्त जीतेंद्र दहिया को शहर में लगे अवैध विज्ञापनों की लोकेशन, फोटो आदि भेज कर बार बार शिकायत की जाती रही। शिकायत सिर्फ निगमायुक्त से ही नहीं की जाती थी बल्कि मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई जाती थी लेकिन लगता है कि अवैध मोटी कमाई का हिस्सा ऊपर तक पहुंचता था तब ही कोई कार्रवाई नहीं होती थी।

दो माह पहले ही निगम सचिव पद पर आए जयदीप से भी विज्ञापन घोटाले की शिकायत की गई लेकिन पूर्व कमिश्नर जीतेंद्र दहिया ने उनकी एक न चलने दी। हाल ही में मोना ए श्रीनिवास ने निगमायुक्त का पद संभाला। निगम के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक मौके की तलाश में लगे जयदीप ने निगमायुक्त को अवैध विज्ञापन घोटाले की जानकारी देकर कार्रवाई के लिए राजी कर अभियान छेड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि कुछ लोगों ने निगम सचिव को सलाह दी कि कहीं भी कार्रवाई करना लेकिन मंत्री प्रोजेक्टों के विज्ञापनों को नहीं छूना वरना अभियान शुरू होते ही बंद हो जाएगा।

इसके बावजूद सबसे पहले उनका बुलडोजर मंत्री के प्रोजेक्ट अमोलिक के अवैध विज्ञापनों पर चला। चार्मवुड विलेज में सड़क के सेंट्रल वर्ज पर हर पांच मीटर पर लगाए गए विज्ञापन, सड़क किनारे लगाई गई होर्डिंग, गैंट्री से लेकर सड़क किनारे खंभों पर लगाए गए पोस्टर सब मिट्टी में मिला दिए गए। इसके बाद अस्पताल, स्कूलों और थाने, चौकियों पर लगाए गए अवैध विज्ञापन हटाए गए। मंत्री को उनके ही गढ़ में उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले ईमानदार अधिकारी की हरकत पसंद नहीं आई। इधर चौकियों से हटाए गए अवैध विज्ञापनों के मालिक अवैध विज्ञापन माफिया भी परेशान हो गए। विज्ञापन माफिया ने जिन निगम अफसरों को लाखों रुपये दिए थे उन पर दबाव बनाना शुरू किया। मंत्री के गुस्से से बचने के लिए इन अधिकारियों ने मंत्री के लगुए भगुओं के जरिए उन तक अपनी स्वामीभक्ति जताते हुए खुद के बेगुनाह होने और सारा दोष जयदीप का होने का संदेश भिजवा दिया। निगम सचिव के साहसिक अभियान लोगों में तारीफ तो हो रही थी लेकिन जल्द ही उनका अहित होने की भी अटकलें लगाई जा रही थीं। हुआ भी वही, बुधवार को निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास ने दो लाइन का आदेशपत्र जारी कर निगम सचिव जयदीप से विज्ञापन संबंधी सभी अधिकार छीन कर अधीक्षण अभियंता ओमबीर को थमा दिए।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री खट्टर यदि सच में ईमानदार हैं तो अवैध विज्ञापनों के खिलाफ अभियान चला कर राज्य सरकार का करोड़ों रुपयों का नुकसान बचाने वाले ईमानदार निगम सचिव जयदीप की छीनी गई शक्तियां वापस दिलाकर यह साबित करें कि वह नगर

विज्ञापन हटाकर मंत्री से ली नाराजगी

निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रति गंभीर हैं, अवैध विज्ञापन माफिया के खिलाफ फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा में अभियान चलवा कर और जुर्माना वसूल कर जनता के समक्ष अपनी ईमानदार छवि प्रस्तुत करें। वह ऐसा कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं क्योंकि अधिकतर विज्ञापन माफिया तो सत्तापक्ष के करीबी हैं।

कई साल से जारी है विज्ञापन से मोटी कमाई का खेल

नगर निगम के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार

शेष पेज दो पर